



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112024-258455
CG-DL-E-05112024-258455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2024/कार्तिक 14, 1946

No. 629]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2024/KARTIKA 14, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 687(अ).—अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त संवर्ग) नियमावली, 1972 के नियम 4 के उप-नियमों (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित क्षेत्रों के संयुक्त संवर्गों के लिए एतदद्वारा निम्नानुसार एक संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण का गठन करती है:-

- संघीय गृह सचिव- सदस्य [भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि]
- वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव- सदस्य [भारतीय वन सेवा के संबंध में सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि]
- मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार- सदस्य
- मुख्य सचिव, गोवा सरकार - सदस्य
- मुख्य सचिव, मिजोरम सरकार- सदस्य

6. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- विशेष आमंत्रित
7. मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर- विशेष आमंत्रित
8. मुख्य सचिव, पुदूचेरी- विशेष आमंत्रित
9. संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र)/अपर सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय-भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में संयोजक।
10. संयुक्त सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग)/वन महानिरीक्षक (भारतीय वन सेवा प्रभाग), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- भारतीय वन सेवा के संबंध में संयोजक। "

[फा. सं. 11031/01/2018-एआईएस-II (भाग-I)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी: अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त संवर्ग) नियमावली, 1972 को दिनांक 11-01-1972 की अधिसूचना सं. 13/4/71-एआईएस (I) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित क्षेत्रों के संवर्गों के संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण को दिनांक 3-4-89 की अधिसूचना सं. 13013/1/89-एआईएस (I), दिनांक 11-12-1992 की सा.का.नि. सं. 919(अ) एवं दिनांक 25-4-1995 की अधिसूचना सं. 11026/2/94-एआईएस-II [सा.का.नि. सं. 361(अ)] के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2024

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the All Indian Services (Joint Cadre) Rules, 1972, the Central Government, in consultation with the Government of States concerned hereby constitutes the Joint Cadre Authority for Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service Joint Cadres of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, as below :—

- “1. Union Home Secretary – Member [representative of all UTs in respect of IAS/IPS]
- 2) Director General of Forest and Special Secretary – Member [representative of all UTs in respect of IFS]
- 3) Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh – Member
- 4) Chief Secretary, Govt. of Goa – Member
- 5) Chief Secretary, Govt. of Mizoram – Member
- 6) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi – Special Invitee
- 7) Chief Secretary, Jammu & Kashmir – Special Invitee
- 8) Chief Secretary, Puducherry – Special Invitee
- 9) Joint Secretary (UT)/Additional Secretary (UT), MHA – Convener in respect of IAS/IPS.
- 10) Joint Secretary (Indian Forest Service Division)/ Inspector General of Forest (Indian Forest Service Division), MoEF&CC- Convener in respect of IFS.”

[F. No. 11031/01/2018-AIS-II(Part-I)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

NOTE: The All India Service (Joint Cadre) Rules, 1972 were notified vide No.13/4/71-AIS(I) dated 11-1-1972. The Joint Cadre Authority of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre was notified vide Notification No.13013/1/89-AIS(I) dated 3-4-89, GSR No.919(E) dated 11-12-1992 and Notification No.11026/2/94-AIS-II dated 25.04.1995 [GSR No.361(E)].